

मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज, ग्राम-पाली, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में स्थित खसरा क्रमांक 25/1, 25/4, 25/5, 25/6, 26/1 एवं 26/3, कुल क्षेत्रफल-2.698 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (15 टन गुणा 3 नग) (स्टील इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता-1,48,500 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (टी.एम.टी. वॉयर रॉड, एंगल, चैनल, स्टील स्ट्रक्चर्स, पत्रा) क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष से 1,46,250 टन प्रतिवर्ष (फर्नेस ऑयल/प्रोड्यूसर गैस) तथा कोल गैसीफायर क्षमता-7,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 07 अप्रैल 2021 का कार्यवाही विवरण :-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज, ग्राम-पाली, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में स्थित खसरा क्रमांक 25/1, 25/4, 25/5, 25/6, 26/1 एवं 26/3, कुल क्षेत्रफल-2.698 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (15 टन गुणा 3 नग) (स्टील इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता-1,48,500 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (टी.एम.टी. वॉयर रॉड, एंगल, चैनल, स्टील स्ट्रक्चर्स, पत्रा) क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष से 1,46,250 टन प्रतिवर्ष (फर्नेस ऑयल/प्रोड्यूसर गैस) तथा कोल गैसीफायर क्षमता-7,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 07.04.2021, दिन-बुधवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान-बंजारी मंदिर के समीप का स्थल, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानों की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्कैनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम मैं प्रशांत शर्मा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज की ओर से माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय श्री आर.ए. कुरुवंशी जी, एस.डी.एम. घरघोडा श्री ए.के. मार्बल जी, क्षेत्रीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल श्री सीतेश कुमार वर्मा जी, एडिशनल एस.पी. महोदय श्री अभिषेक वर्मा जी उपस्थित अन्य अधिकारीगण तथा पुलिस प्रशासन का और साथ ही उपस्थित जनता का मैं इस लोकसुनवाई में स्वागत करता हूँ। हमारे द्वारा ग्राम-पाली, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में रोलिंग मिल क्षमता (30000 टन/वर्ष) का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सम्मती नवीनीकरण जारी किया गया है

3. 8. 1945

जिसकी वैधता दिनांक 31.05.2025 तक है। वर्तमान में कम्पनी द्वारा विद्यमान परिसर में ही स्टील इंगोट्स एवं बिलेट्स के उत्पादन हेतु 3 गुणा 15 टन इण्डक्शन फर्नेस (क्षमता-148500 टन/वर्ष), टी.एम.टी. बार/वायर रॉड/एंगल/चैनल/स्टील स्ट्रक्चर/पतरा उत्पादन हेतु संचालित रोलिंग मिल (ईंधन के रूप में एल.डी.ओ./प्रोड्यूसर गैस) में क्षमता विस्तार (क्षमता-30000 टन/वर्ष से 146250 टन/वर्ष) तथा कोल गैसिफायर (क्षमता-7000 सामान्य घनमीटर/घण्टा) की स्थापना प्रस्तावित है। वर्तमान में हमारे पास 2.698 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है तथा इसी भूमि पर ही क्षमता विस्तार प्रस्तावित है एवं अतिरिक्त भूमि क्रय नहीं की जावेगी। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के लिए वर्तमान पर्यावरण नियमानुसार हमारे द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। इसी तारतम्य में यह लोक सुनवाई आयोजित की गई है। हमारे द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए संचालित रोलिंग मिल में स्क्रबर का उन्नयन तथा नई इण्डक्शन फर्नेस इकाई में नये बैग फिल्टर की स्थापना प्रस्तावित है। सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता पार्टिकुलेट मीटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम के अनुरूप होगी। विद्यमान इकाई के लिए 20 किलो लीटर/दिन जल की आवश्यकता होती है। जिसे भू-जल स्रोत से लिया जाता है। प्रस्तावित परियोजना के लिए 75 किलोलीटर/दिन जल की आवश्यकता होगी, जिसकी भी आपूर्ति भू-जल स्रोत द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तारोपरांत जल की कुल आवश्यकता 95 किलोलीटर/दिन होगी। केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण द्वारा जल राशि के आहरण की अनुमति प्रदान की गई है। रोलिंग मिल से उत्पन्न दूषित जल को सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है जहाँ से उसे पुनर्चक्रित किया जाता है। घरेलू दूषित जल (1.6 किलो लीटर/दिन) का उपचार सेप्टिक टैंक तथा सोकपिट द्वारा किया जाता है। शून्य निस्तारण संकल्प का परिपालन किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना में क्लोज्ड सर्किट सिस्टम को अपनाया जावेगा जिससे एस.एम.एस. इकाई द्वारा किसी प्रकार का दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। रोलिंग मिल इकाई के प्रस्तावित क्षमता विस्तार द्वारा उत्सर्जित औद्योगिक दूषित जल को सेटलिंग पाण्ड में भेजा जावेगा। जहाँ से उसे क्लोज्ड कूलिंग सर्किट द्वारा पुनर्चक्रित किया जाना प्रस्तावित है। दूषित जल में आईल एवं ग्रीस तथा क्लीनिंग एजेंट के उपचार हेतु आईल एवं ग्रीस ट्रैप्स का प्रावधान किया जावेगा। परियोजना विस्तार द्वारा घरेलू दूषित जल का उत्सर्जन 04 कि.मी./प्रतिदिन होगा एवं इसका उपचार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा किया जायेगा। उपचारित सीवेज का पुनर्उपयोग वृक्षारोपण हेतु किया जावेगा। शून्य निस्तारण स्थिति बनाई रखी जावेगी। परिसर में लगभग 0.90 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है तथा अभी तक हमारे द्वारा लगभग 1000 नग वृक्षारोपण किया गया है। आगामी मानसून में विकसित वृक्षारोपण की ओर सघन किया जावेगा। हमारे द्वारा संचालित इकाई में आस-पास के लोगों को योग्यतानुसार रोजगार दिया गया है तथा प्रस्तावित परियोजना में भी स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी। सामाजिक दायित्व के निर्वहन नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया जावेगा। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सुझाये गये सभी उपायों को अपनाया आयेगा जिससे परियोजना द्वारा निकटस्थ क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे। अंत में प्रस्तावित परियोजना के लिये उपस्थित जनता से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से

अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 500-600 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 103 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है -

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री -

1. पंचुराम यादव, पाली - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
2. कृष्णा, पाली - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
3. गोवर्धन प्रधान, पाली - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
4. कन्हैया, पाली - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
5. नरेश कुमार, पाली - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
6. प्रेम कुमारी, तराईमाल - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करती हूँ।
7. गुरवारी, तराईमाल - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
8. मीनाबाई, तराईमाल - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
9. लीला पाल, तराईमाल - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
10. रेवती, तराईमाल - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
11. सरिता भगत, तराईमाल - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
12. मीना, तराईमाल - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
13. मुरका, तराईमाल - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
14. मीना - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
15. रत्ना, तराईमाल - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
16. मेवा, इन्द्रावासस - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
17. रामवती, तराईमाल - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
18. हसीना, तराईमाल - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
19. किर्ती, तराईमाल - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
20. वृन्दा, तराईमाल - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
21. रत्ना, तराईमाल - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
22. सीमा - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

56. पार्वती, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
57. चमेली, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
58. सुशीला – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
59. नीलम – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
60. मंजु पटेल, पूंजीपथरा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
61. हरिप्रसाद, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
62. दयाराम – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
63. शिवा, सामारुमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
64. राजकिशोर, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
65. बबलु, सामारुमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
66. पुरुषोत्तम – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
67. देवकुमार – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
68. खगेश्वर – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
69. गोपाल, सामारुमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
70. संतकुमार, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
71. चन्द्रभान, सामारुमा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
72. भजन लकड़ा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
73. सीता, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
74. अंजनी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
75. तारीका तरंगिनी लकड़ा, पूंजीपथरा, सामारुमा – आज दिनांक 07.04.2021 को मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज ग्राम-पाली, तहसील व जिला-रायगढ़ की स्थापना के लिये आयोजित फर्जी लोक सुनवाई रद्द करने बाबत। मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज ग्राम-पाली, ग्रामपंचायत-देलारी, तहसील-रायगढ़, जिला-रायगढ़ के लिये आज जो लोकसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है इसकी पूरी प्रक्रिया फर्जी की जा रही है। उक्त परियोजना से संबंधित जानकारी किसी भी प्रभावित ग्रामवासियों को नहीं है। लोक सुनवाई का आयोजन भी संबंधित पंचायत या ग्राम में किया जाना चाहिए। मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज की मांग प्रभावित क्षेत्र के किसी भी पंचायत या ग्रामसभा ने नहीं की है। एक उद्योगपति के प्रस्ताव से अनुसूचित पंचायत में ग्रामवासियों की मांग के बिना उक्त परियोजना को पर्यावरण प्रदूषण की स्वीकृति देना असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। आज मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज को पर्यावरण प्रदूषण करने की स्वीकृति देने के लिए बिहार, उड़ीसा, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश के लोगों को तथा संबंधित प्रभावित पंचायतों से बाहर के लोगों को यहाँ का स्थानीय निवासी बताकर समर्थन कराया जा रहा है। आपके द्वारा स्थानीय होने का कोई पहचान पत्र इन समर्थकों से नहीं पूछा जा रहा है। विरोध करने आने वाले स्थानीय लोगों को यहां डराया-धमकाया और दुरव्यवहार किया जा रहा है। हमारा क्षेत्र पहले ही प्रदूषण की वजह से विश्व के सबसे प्रदूषित जिलों में शामिल है। यहाँ प्रदूषण की वजह से

कई लोगों की मौत हो चुकी है लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हैं। स्वच्छ जल, पीने के लिये भी अब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। खेती प्रदूषण की वजह से नहीं हो पा रही है। तालाब, डेम, नदियाँ सभी प्रदूषित हो चुके हैं। सड़कों पर सुरक्षित चलना मुश्किल हो गया है। रायगढ़ तक जाने पर व्यक्ति डस्ट से पहचान में नहीं आते हैं। घरों में डस्ट की परत जम रही है। पेड़ों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण मण्डल छत्तीसगढ़ को हम छत्तीसगढ़ की जनता ने पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी के विपरित पर्यावरण प्रदूषण करने की स्वीकृति दिलाने आये हैं। विरोध करने पर आप पुलिस बल का प्रयोग करेंगे, मुझे घसीट कर पुलिस से पिटवा कर इस पंडाल से बाहर करेंगे। इसका मतलब आपने पहले ही अग्रोहा ऑयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज के साथ हमारी जिंदगी का सौदा किया हुआ है। आपकी जिम्मेदारी है हमें पर्यावरण की सही रिपोर्ट बताएँ। हमारे क्षेत्र के लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं उन्हें ग्रामसभा लगाकर, सरल भाषा में बताना ये आपका फर्ज था। आपने ऐसा नहीं किया। दिनांक 05.04.2021 को मुझे मालुम हुआ की आज दिनांक 07.04.2021 को बंजारी मंदिर प्रांगण में कोई लोक सुनवाई का आयोजन पर्यावरण प्रदूषण करने की स्वीकृति के लिये किया गया है। दिनांक 05.04.2021 को ही मैंने आपके कार्यालय में आवेदन दिया है कि उक्त लोकसुनवाई से संबंधित जानकारी मुझे उपलब्ध कराई जाए। आपके कार्यालय से ना तो जानकारी मिली है ना ही कोई और अवाब मुझे दिया गया है। मैं संबंधित प्रभावित पंचायत से हूँ, मेरा अधिकार है कि आप मुझे जानकारी उपलब्ध कराएँ। मेरे मांगने पर भी मुझे जानकारी नहीं दी गई है। आपके द्वारा जिन पंचायतों में ई.आई.ए. रिपोर्ट दी गई है उन पंचायतों के सरपंच भी उसे सगझने में सक्षम नहीं हैं। ना ही वे ये जानते हैं कि इस रिपोर्ट का करना क्या है? आपने कभी भी इसके संबंध में पंचायतों के सरपंच, सचिवों को कोई दिशा निर्देश दिया ही नहीं है, ना ही ग्रामसभा के लिए निर्देश दिये हैं। ये सीजन वनीय फसलों का है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव से इस वर्ष महुआ, चार की फसल का लाभ ग्रामीणों को जो मिलता था वो नहीं मिला। क्या अग्रोहा ऑयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज इसकी भरपाई करेगा? मैं प्रभावित पंचायत की निवासी हूँ। उक्त परियोजना से मुझे मेरे परिवार को मेरे गांव को जो प्रदूषण सहना होगा इससे हमारे बच्चे, जवान, बुढ़े बीमार होंगे, मरेंगे, मवेशी मरेंगे इसकी भरपाई आपने करवाई है क्या? यदि करवाई है तो हमसे छुपाया क्यों है हमें बताईये इसका मुआवजा आपने कितना तय किया है? हमें हमारा मुआवजा पहले दिलाईये। प्रत्येक घर, वार्ड तक यह मुआवजा पहुंचाना चाहिए। आपने हमारी जिंदगी का सौदा करने के लिये इस लोकसुनवाई में बाहरी व्यक्तियों को भाड़े में लाकर समर्थन करवाने की खुली छुट इस उद्योग मालिक को दी है। जो चाय-नाश्ता, 100-200 रुपये इनसे लेकर यहां सिर्फ समर्थन है कहकर चले जाते हैं। कुछ कहते हैं हमें रोजगार मिल रहा है इसलिये समर्थन करते हैं। क्या यह लोक सुनवाई रोजगार दिलाने के लिये रखी गई है? यह पूरी लोक सुनवाई फर्जी है। यहाँ आने वाले समर्थक फर्जी है। आपके द्वारा की गई प्रक्रिया फर्जी है। बंजारी माँ के प्रांगण में लोक सुनवाई का आयोजन कराना नियम के विरुद्ध है और फर्जी है। सामारुमा में फर्जी सरपंच बनवा कर उसके माध्यम से फर्जी समर्थकों को लाकर लोक सुनवाई को सफल बनाने का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को आप कोई महत्व नहीं देते हैं। अतः इस फर्जी लोक सुनवाई को रद्द करने की मांग मैं तारिका तरंगनी संघर्ष के माध्यम से करती हूँ।

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

406. गजपति, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
407. देवेन्द्र, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
408. ओमप्रकाश, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
409. डोरीलाल, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
410. राजेन्द्र कुमार, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
411. सोनु, तराईमाल – विरोध।
412. संजीत सिदार, तराईमाल – विरोध।
413. ओमप्रकाश – विरोध।
414. अवधेश, तराईमाल – विरोध।
415. संजय – विरोध।
416. डोरीलाल – विरोध।
417. जय-विरोध।
418. विवके, तराईमाल – विरोध।
419. बिरजू, – विरोध।
420. शंकर, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
421. स्वराज, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
422. रवि, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
423. रवि, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
424. सुरेन्द्र, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
425. राजेश, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
426. समय, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
427. सागर, लाखा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
428. गौरीशंकर, पाली – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
429. फुलेश्वर, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
430. अमृतलाल, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
431. बुद्ध, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
432. माधुरी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
433. गौरी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
434. रजनी, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
435. यशोदा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
436. म्हुबुब – पानी का सुविधा करवाते हैं। मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
437. नेत्रानन्द, देलारी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
438. रामसाय डनसेना – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

439. पितरू, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
440. श्रीलाल, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
441. शेषदेव, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
442. फुलेश्वर साहु, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
443. मुकेश, गेरवानी – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
444. विजय कुमार, – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
445. चवंर सिंह, गेरवानी – इस क्षेत्र में बहुत उद्योग है, लेकिन इस क्षेत्र के स्थानीय लोगो को रोजगार नहीं मिलता है। प्रदूषण बहुत होता जिसका कोई रोकथाम नहीं है। सड़क दुर्घटना बहुत होती है उसके लिये कोई उचित कदम उठाये। सभी को रोजगार उपलब्ध कराये। मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
446. पंचराम मालाकार, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
447. गोपी प्रधान, पाली – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
448. कन्हैया, पंच तुमीडीह – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
449. खीरसागर – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
450. दीपक शर्मा – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
451. भुपेन्द्र कुमार मालाकार, तराईमाल – पानी छिड़काव नहीं कराते प्लांट वाले, बहुत प्रदूषण है सड़क में उसका कोई रोकथाम नहीं है। यहां हॉस्पिटल नहीं है। मैं विरोध करता हूँ।
452. अंकुर गोटिया, तराईमाल – मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ। पहले यहां सब भुखे मरते थे आज सब सम्पन्न है। यहां किसी की शादी होया या मृत्यु को चंदा एककट्टा करके सहमति प्रदान करते है।
453. सविता रथ, जन चेतना मंच, रायगढ़ – इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु जो ईआईए. ड्राफ्ट है और इस कोरोना काल में जहा जिला प्रशासन धारा 144 लगा रखी है उस स्थिति में लोगो के जीवन के साथ खिलवाड़ खास कर जनता से भी ज्यादा आपके खुद के प्रशासनिक अधिकारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना इस जनसुनवाई को करवाना वास्तव में किस हद तक खतरनाक है और किस हद तक आप मजबूर करते है पुलिस प्रशासन को यहा पसर काम करने के लिये और जिस तरीके के हालात है उससे सीधे देखा जा रहा है मेरे पीछे जो पंडाल है, उस पंडाल के पीछे जित तरीके के हालात है। चूंकि यहा अनुसुचि पेशा क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है फिर भी जिला प्रशासन से ज्यादा जो समुदाय है वो ज्यादा सतर्क है, सुरक्षित है इस वैश्विक महामारी के हालात पे जनसुनवाई करवाना। और हमारे बहुत सारे युवा साथी है अलग-अलग कामों में इस जनसुनवाई को सीधे-सीधे संपन्न करवाने के लिये और उनके द्वारा जिस तरीके से यहा व्यवस्था में लगे हुये है कही ना कही हम उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे है और इसमें जो महिलाये लगी हुई है पुलिस प्रशासन हो चाले अन्य कामों में जनसुनवाई को शांतिपूर्ण अच्छे से संपन्न करवाने के लिये उन महिलाओं के सेहत के उपर बात आती है फिल भी आपलोगो ने जनसुनवाई करवाया है तो मैं बरलिया की रहने वाली हूँ और सीधे प्रभावित हूँ इसलिये ये बात रख रही हूँ। आज की जनसुनवाई इस मेसर्स अग्रोहा

आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज ग्राम-पाली में जो स्थापित होने वाला है इसकी लोगो से चर्चा के दौरान आया है। हमने ई.आई.ए. की समरी ही लिया है ये समरी जिस आधार पर बना है यह अग्रोहा आयरन स्टील इण्डस्ट्रीज का बनाने वाले, एन.आर.टी.एम.टी. इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का बनाने वाले, एन.आर. फेरो का बनाने वाले और मों शिवा जो आज कल एनॉकान लेबोरेटरी, नागपुर के साथ मिल कर काम कर रहा है, इसके साथ बी.एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड और इस तरीके के मेरे पास 5-7 और है। इस मेसर्स अग्रोहा आयरन स्टील इण्डस्ट्रीज की जनसुनवाई आज दिनांक 07.04.2021 को बंजारी, तराईमाल में आयोजित इस जनसुनवाई को महामारी के कारण तत्काल निरस्त करके पुनः कमियों को दूर करके इसे आयोजित कराया जाये। मेरा पहला आपत्ति है जहा एक तरफ धारा 144 लगी हुई है जहा पर सादी में 50 और मौत में 20 लोगो की बात कर रहे है और पुरे छत्तीसगढ़ में देखा जाये तो 10000 से ज्यादा आंकड़े है, शमशान घाट कम पड़ जा रहा है तो इस जनसुनवाई को करवाने का क्या औचित्य रह जाता है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है कि लोग रहेंगे, गांव रहेगा तो आप और हम सब विकास कर लेंगे और इस एक विकास के लिये बाकी लोगो का विनाश करने आप किस हद तक तुले हुये है। आप राज्य शासन, केन्द्र शासन को लिख कर नहीं दिया कि इस महामारी काल में यह पेशा क्षेत्र और पेशा क्षेत्र में ग्रामसभा महत्वपूर्ण है। आपने ग्रामसभा से अनुमति लिया है क्या जनसुनवाई करवाने के लिये, पंडाल लगाने के लिये, पुलिस फोर्स बुलाने के लिये ऐसे कोई पेपर है क्या आपके पास अगर नहीं है तो आपको भी अधिकार नहीं है कि अनुसुचि पेशा क्षेत्र में जिला प्रशासन या राज्य शासन का अधिकार ही नहीं है कि बिना ग्रामसभा के अनुमति के आयोजन करना। यह आप लोग औद्योगिक घराने को खुश करने के लिये यह जन सुनवाई आप करा रहे है। उसे निरस्त करें और महामारी काल समाप्त होने के पश्चात् इसे आयोजित करें। आप कितने लोगो तक ई.आई.ए. रिपोर्ट लेकर गये इस बात का रिजल्ट मेरे पीछे है। 10 किलोमीटर के रेडियस को भी देखे तो 10 किसम के लोग भी यहा नहीं है तो किसके लिये जनसुनवाई है। किसी भी शरकारी आयोजन के लिये 70 प्रतिशत संख्या होना चाहिए और किसी भी गैर सरकारी के लिये 80 प्रतिशत संख्या है। 80 प्रतिशत प्रभावित लोगो को आपको लाना था और उसमें 33 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की लागु होना था। यह जनसुनवाई इनवायरमेंट इंपेक्ट असिसमेंट की जनसुनवाई है, ई.आई.ए. पर कितनी समझ है लोगो की और इसको बनने के लिये हमे किस तरीके से एस.आई.ए. बनाना था उसकी प्रक्रिया क्या थी, कहा है वो कमेटी जिसको सामाजिक प्रभाव आंकलन 10 गांव का करना था। इसके बात ही ई.आई.ए. बनाने की अनुमति मिलना था। हमारे समाज में किसी भी कंपनी को अगर गैर कृषि है, गैर वाणिज्यिक है, गैर आदिवासी परम्परा से बना चिज है तो एन चिजो को गुल रूप से जीवन को प्रभावित कितना कर रहा है, उनके आजीविका का मामला है, उनके अन्य जो पारंपरिक मसले है, उन मसलों को कैसे ठीक किया जायेगा, कैसे उनके देव स्थल बचाये जायेंगे वो एस.आई.ए. पहले निकालिये वो एस.आई.ए. कहा बना है वो एस.आई.ए. बनाने वाली कमेटी कहा है, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के जीवन में कंपनी का क्या प्रभाव पड़ेगा जब आप फर्नेस ऑयल, प्रोड्यूसर गैस तथा कोल गैसीफायर जिसकी क्षमता 7000 प्रति सामान्य घनमीटर रफ्तार से आप इसकी स्थापना कर रहे है, पर्यावरणीय स्वीकृति चाह रहे है कहा है वो गर्भवती महिलाओं का सलाह, क्या आपको उन्होने ग्रामसभा से अनुमति दिया, क्या उन्होने अपना राय लिखित रूप में रखा, नहीं रखा तो किस बात

की जनसुनवाई। आप जिला प्रशासन और कंपनी मिल कर सरफेयस राईट बना ले क्यों जनसुनवाई कराने की क्या जरूरत। आपको अधिकार नहीं है किसी के साथ जीवन का खिलवाड़ करने का आप 5 बजे तक जनसुनवाई करवायेंगे 6 बजे के बाद इन्की सेहत का जिम्मेदार कौन होगा। और कितनी जनसुनवाईयां आप लोगो के द्वारा होनी है यह हैरान करने वाली बात है। पाली गांव का जी.पी.एस. में देखिये पाली गांव रायगढ़ विकासखण्ड में आता है और आज जहा जनसुनवाई करा रहे है वह तमनार विकासखण्ड में आता है, पाली गांव गैर पेशा एक्ट क्षेत्र में आता है और यह जो है यहा पेशा कानून लागू होता है। आपके खिलाफ एस.टी.एस.सी. का अपराध कायम होना चाहिये कि आब जबरन इस कोराना काल में यहा बीमारी थोप रहे है उनके बिना अनुमति के आपको अधिकार नहीं है इतने बड़े आयोजन कराने का, हम तो आपके कलेक्ट्रेड जाकर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करवा रहे है। अगर जिस दिन हम ऐसा कर दे कलेक्ट्रेड के पास लोगो की सहन सीमा खतम हो रही है अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों को कलेक्ट्रेड में जाकर करें तो सोभा नहीं देता। पाली गांव का एस.डी.एम. रायगढ़ का जहा जनसुनवाई करवा रहे है वहा घरघोड़ा के एस.डी.एम. है तमनार विकासखण्ड के तहसीलदार है। यहा कौन से डॉक्टर है जिनके द्वारा लोगो का हेल्थ चेकअप करने के बाद यहा आने दिया जा रहा है या फिर सामाजिक कार्यक्रम सादी, विवाह आदि की अनुमति दे दीजिये। साले नियम कानून जनता, समुदाय करे। इस मेसर्स अग्रोहा आयरन स्टील इण्डस्ट्रीज का विवाद कौन सुलझायेगा रायगढ़ एस.डी.एम. करेंगे या घरघोड़ा एस.डी.एम. करेंगे। इस कोरोना महामारी में जो आप जनसुनवाई करा रहे है इसको तत्काल निरस्त करें अच्छा है कि यहा भीड़ बहुत कम है यहा जितने भी है उन सबका आप कोरोना जाँच करवाईये हो सकता है आपके अंदर वो वायरस हो हो सकता है मेरे अंदर वो वायरस हो मैं बिना मेडिकल टेस्ट कराये आई हूँ और भी बिना मेडिकल टेस्ट कराये आये है। इसके बाद ही कोई बिन्दु पे बात रखेंगे। केन्द्रीय मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के तहत किसी कंपनी के आवेदन जमा करने के 45 दिवस के अन्दर राज्य शासन के द्वारा ही कराया जाना है। आप जो ई.आई.ए. की जनसुनवाई जान पर खेल कर कर रहे है ऐसा लग रहा है कि आप बाघा बाडर में है या चाईना बाडर में है इस तरह से आप अपने जान को खेल रहे है इस जनसुनवाई में। यह जो आवेदन आया है वह 1 वर्ष पुराना है, आपका कानून कहता है 45 दिन तो इस जनसुनवाई को आपको आयोजित कराने का कोई औचित्य ही नहीं रहा जाता है। उस स्थिति में यह जनसुनवाई केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी का गठन करेगा वह आकर इस जनसुनवाई को आयोजित करायेगी ना कि आप करायेंगे और आप बैठे है जनसुनवाई करवाने के लिये अगर हम आपत्ति भी करेंगे तो इसका जवाब कौन देगा इनके आवेदन को 1 वर्ष हो चुका है क्या आप सक्षम अधिकारी है। प्रभावित लोगो का राय आया क्या लिखित या मौखिक, विरोध कर रहे है तो किस बात की विरोध हो रही है क्या उनको पता है कि यह उद्योग लगना है यह ई.आई.ए. पर बात हो रही है। इसमें न तो आपको अधिकार है आपको जनसुनवाई कराने का ना ही प्रभावित क्षेत्र के लोग आये है यहां अपनी बात रखने। 10 किलोमीटर की परिधि में 56 गांव प्रभावित होते है यहां तो 56 लोग ही नहीं है, तो काहे इतने बड़े आयोजन को करा रहे है आप लोग आपस में उद्योग को कलेक्ट्रेड में बुला लीजिये और कर लीजिये। यहा एक भी महिला नहीं है और है भी तो वो प्रशासनिक अधिकारी है। पाली का जनसुनवाई पाली में क्यों नहीं हो रहा है। उस क्षेत्र के 10 गांव

को सामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, वहा का 18 नाला क्यों शामिल नहीं है इसमें, वहा के पलाई ऐश का मामला क्यों नहीं है। जिस दिन जनसुनवाई होती है उस दिन उद्योगो द्वारा ई.एस.पी. को चालु कर दिया जाता है। अभी आप मेरे साथ चलिये आपको मैं बिना ई.एस.पी. चले 10 उद्योग दिखा दूंगी वे समझ गये है जिला प्रशासन के कार्यप्रणाली को पुरा तराईमाल क्षेत्र में कोयला का धुआं चल रहा है। गेरवानी से लाखा, पूंजीपथरा में कहीं भी ई.एस.पी. नहीं चल रहा है। प्रदूषण ही प्रदूषण है। 56 गांव में कही भी हिन्दी या अंग्रेजी का ई.आई.ए. रिपोर्ट नहीं चस्पा कराया गया है। लोगो को ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने वाले ने एन. आर. टी.एम.टी. एवं एन.आर. फेरो एलायज, मां शिवा कंपनी, बी.एस.स्पंज प्रा. लिमिटेड के रिपोर्ट को जोड़-तोड़ के कापी पेस्ट करके यह ई.आई.ए. रिपोर्ट का बनाया गया है। हाथी, गिलहरी, चितल, किट-पंतगे आदि के बारे में इस ई.आई.ए. में दर्शित नहीं है। यहां 40 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल है, इंजीयरिंग कॉलेज का डेटा, यहां के बच्चो का डेटा इसमें दर्ज नहीं है। यहां के स्वास्थ्य परीक्षण कराकर रिपोर्ट इस सुनवाई में प्रस्तुत करना था लेकिन नहीं किया गया है। यहां से 02 कि.मी. में गोदगोदा, पड़कीपहरी सी.एफ.आर. का वन क्षेत्र है। आप किस आधार पर जनसुनवाई करा रहे है। पेशा कानून, महिला हिंसा, फारेस्ट कानून, 1976 वन पशु की धारा आप पर लगेगा। हाथियों के द्वारा नुकसान हेतु 40 लाख का कारीडोर बनाया गया है। यह जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करें। यहां आंगनबाडियों के 3-6 वर्ष के बच्चों के सेहत से भी खिलवाड किया जा रहा है। यहां 40 आंगनबाडिया है जिसे ई.आई.ए. में छिपा दिया गया है। इस क्षेत्र में सिलिकोशिश के साथ चर्म रोग, दमा रोग आदि है। यहां से जांच के लिये कितने जगहो से मिट्टी, जल के नमूने लिया गया है। यहां पास में केलो नदी है जिसमें पलाई ऐश डाला जा रहा है। यहां जितने भी स्तनधारी जीव है जिनके जिंदगी से आप खिलवाड़ कर रहे है। यहां के सब्जियों की स्थिति में बहुत गिरावट हो गई है। यहां औद्योगिक पार्क में उद्योग अपनी मनमानी कर रहे है। यहां सिलिकोशिश का बीमारी फैलते जा रहा है। ई.आई.ए. बनाने वाले भी उद्योगो से धोखा कर रहे है। केलो बांध से किसानों को पानी दिया जायेगा बोला गया, लेकिन यह पानी निको देंगे वहां तक का जमीन बंजर हो जायेगा। केलो नदी के पानी से कई बीमारियो जैसे कैंसर हो रहा है। यहां अलग-अलग राज्यो से आकर काम कर रहे है। सी.एस.आर. करेंगे, रोजगार देंगे, लेकिन महिलाओं के लिये क्या करेंगे। आज उनसे उनका जल जंगल से चार, तेन्दु पत्ता भी खतम हो गया। यहां के जंगली जीव धीरे-धीरे महासमुन्द से होकर गरियाबंद में चले गये है। यहां आपने कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग को किसी कंपनी से चालु नहीं किया तो क्या विकास और किसका विकास हो रहा है। यहां के स्थानीय लोगो का पैसा क्यों खत्म कर रहे है। यहां के लोगो के पास जाकर क्या आपने ई.आई.ए. के बारे किसी को बताया ही नहीं तो किस बात की जनसुनवाई! यहां के कृषि, वनोपज संग्रहण, वनो से जीने वाले वन निवासी द्वारा मुझे भेजा गया है जिसमें जनसुनवाई निरस्त करने की मांग है।

454. प्रकाश त्रिपाठी, सर्वोदय विकास समिति, रायगढ़ - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का पूर्ण विरोध करता हूँ। यहां उद्योग अति से अति ज्यादा हो गये है। भारत में सबसे खतरनाक प्रदूषण की स्थिति का सामना रायगढ़ कर रहा है। शिक्षा के स्तर यहां बहुत नीचे है, यहां शोषण करते आ रहे है। इस क्षेत्र में जो उद्योग लग रहे है जिरासे अत्यन्त विनाशकारी स्थिति हो गई है। यहां का सर्वे करा के देख लीजीए

जिसमें मानव में बांझपन की स्थिति आ गई है। 40-45 के उपर के लोग आज काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके जहर युक्त हवा/पानी मिल रहा है। पहले के 90 वर्षीय लोग खेती करते थे। यहां जंगल समाप्त हो रहे हैं जंगल से ही तो ऑक्सीजन मिलता है। बस्तर में जाकर उद्योग स्थापित करें। यहां खेती करके लोग अच्छी तरह से जी रहे थे। यहां उद्योग 01 का विकास के लिए 01 लाख का विनाश कर रही है। इस क्षेत्र में 50 कि.मी. के परिधि में कोई भी जंगली जानवर नहीं है सबका विनाश हो चुका है कुछ समय बाद मनुष्य भी गायब हो जायेगा। हमारे यहां की वन औषधियां जैसे हर्रा बेहरा, आदि सब समाप्त हो गया है। इस क्षेत्र में सिर्फ काला धुआं दिखता है। यहां सर्वे करा लिया जाये प्रत्येक गांव में 60 प्रतिशत लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। यहां वन जमीन, निजी जमीन शासकीय जमीन सबको यहां उद्योगों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस क्षेत्र में पहले बहला जमीन होती थी लेकिन आज रायगढ़ जिले में 01 प्रतिशत बहला जमीन नहीं है। इन उद्योगों के चलते सामाजिक संतुलन बिगड़ चुका है। इस क्षेत्र में रायगढ़ जिले का प्रथम स्थान सब्जी के लिये माना जाता था, लेकिन आज कहीं थोड़ा सब्जी भाजी लगा ले तो वो खाने लायक नहीं होता। यहां पहले 12 महीने खेती होता था वो नस्ट हो गया हैं। क्षेत्रीय मजदूरों का शोषण किया जाता है, मानव को कहीं भी 12 घंटा काम के लिये नियम है लेकिन यहां कराया जाता है और कोई बोले तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। यहां पूंजीपथर से रायगढ़ के बीच में हर दिन 2-3 लोग दुर्घटना से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे उद्योग के मालिकों को फांसी की सजा दी जाये। यहां के लोग दोना, पत्तल, बहरी, चटाई बनाकर अपना जीवन-यापन करते थे, लेकिन अब तो कच्चा माल ही नहीं है तो क्या बनायेंगे। इन उद्योगों के चलते ही नशाखोरी बढ़ गया। सामाजिक अपराध भी बढ़ गया। कुछ लोगों के पास अनाब-रानाब पैसा आने के कारण जुआखोरी में चला जा रहा है। यहां एक छोटा सा मार-पीट हो जाता है तो टी.आई. साहब बोलते हैं की यह मेरा क्षेत्र का नहीं है, तो क्या यह जनसुनवाई रायगढ़ क्षेत्र का है तो तमनार में क्यों किया जा रहा है। उद्योग से होने वाले लाभ और हानी को संबंधित ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाये तो ये दशा नहीं होगा। इस जन सुनवाई को निरस्त करें। इस महामारी काल में क्या जन सुनवाई कराना जरूरी था क्या।

455. गुलामन चौहान, सामारूमा — मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

456. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना, रायगढ़ — सबसे पहले बीजापुर में शहिद नवजवानों को नमन करता हूँ। आज की जनसुनवाई में 2 तरीके के मुद्दे हैं एक तो कानून की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के मुताबिक आज की जनसुनवाई में आर्टिकल 21 का सीधा-सीधा उल्लंघन है। विगत 10 दिनों से फैलाया जा रहा है कि कोराना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और रायगढ़ जिले में विगत 15 दिनों से धारा 144 लगाया गया है उन परिस्थितियों में भी जनसुनवाई का आयोजन करवाना ये कहा उचित है और हमारी कौन सी प्रशासनिक मजबूरी है। क्या जो आज की जनसुनवाई में जो हिस्सेदारी किये वो अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और किसी की मृत्यु हो जाती है तो जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी लेंगे या कलेक्टर साहब लेंगे कि पर्यावरण अधिकारी लेंगे। कौन लेगा जिम्मेदारी। जिसके तहत 302 के तहत एक तरीके से मारने का मामला पंजीबद्ध हो सकता है और ऐसी कौन सी प्रशासनिक मजबूरी है। जिनकी एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले जनसुनवाई हुई है उनका उद्योग स्थापित हो चुका है, जिनका कुछ 10 दिन पहले जनसुनवाई हुई है

बिना पर्यावरणीय स्वीकृति मिले उनका आधा उद्योग खड़ा हो चुका है आप देख सकते हैं, हम तो देख ही रहे हैं तो कैसे मास्क लगाईये, दो गज की दूरी बनाईये मुझे लगता है कि यह एक प्रायोजिक प्रक्रिया है।। पिछले साल कोरोना आया तो आप हाथ को सेनेटाईज कर लीजिये और हो सके तो पेट को भी कर लीजिये कोरोना नहीं होगा पुरे देश में शराब की बिक्री दस गुना ज्यादा बढ़ गई तो सरकार की क्या ये योजना थी। इस साल जो कोरोना की दवाईयां बनी उन दवाईयों में सीधे जो प्रयोग की प्रक्रिया है वो सीधे इंसान पर की गई जो हिन्दुस्तान के अंदर 10 करोड़ लोगो को कोरोना के टीके लग जायेंगे उन दवाईयों को हम पुरी दुनिया में बेचेंगे और अच्छी खासी आय हमे प्राप्त होगी और एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जहा-जहां कोरोना फैल रहा है और कोरोना भी कितना सम्मानजनक फैल रहा है। और आज क्या है कोरोना की स्थिति घर से कोई नहीं निकलेगा, कोरंटाईन में पुरा परिवार कहीं नहीं निकलेगा। अगर कोई कोरंटाईन है और अगर घुमते पाया गया तो अपराधिक मामले दर्ज होंगे और 10 हजार रुपये का उसके उपर जुर्माना लगाया जायेगा ये हमारे जिला कलेक्टर साहब का आदेश है और एक तरफ आप कह रहे हैं है आईये और जनसुनवाई में बात करीये। ऐसे कौन सी मजबूरी है कि आज ही जनसुनवाई हो चार महिने बाद भी तो हो सकती है। और आदेश यह भी निकाल देना चाहिये कि जिन उद्योगों की ई.आई.ए. पर्यावरण विभाग में जमा हो गई है वो अपना उद्योग स्थापित कर ले, परमिशन तो मिलनी ही है और जब कोरोना काल खतम हो जायेगा तो उनकी जनसुनवाई की जो प्रक्रिया है, जनसुनवाई का जो तमाशा है उसको हम पुरा कर लेंगे इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय को भेज देंगे और जनसुनवाई की प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी। एक तरफ पुरे जिले में कोरोना फैला है, अलग-अलग हमारे पुलिस के नौजवान साथी वो हमारे ही लोग हैं किसी उद्योगपति का बेटा या मंत्री का बेटा फौज में नहीं होता है। ये जो सेना में है वो किसी मजदुर और किसान के बेटे हैं और उनके अंदर परिवार है, अगर कोई कोरोना पाजिटिव होगा तो सरकार के अंदर एक प्रक्रिया है। मैंने अभी समाचार में पड़ा की नक्सलियों को सामान पहुंचाने वाला कोई नहीं बल्कि पूर्व विधायक का भाई नक्सलियों को सामान पहुंचा रहा था। हमारे देश की सरकार क्या कर रही थी कि 10 सालो से जो नक्सलियों को सामान पहुंचा रहा है वो आज तक पकड़ा नहीं जा रहा था कहा थी हमारी पुलिस की व्यवस्था क्या ऐसे लोगो को राज्यनैतिक संरक्षण प्राप्त था। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहुंगा पुलिस के नौजवानों को कि आप आपनी रक्षा स्वयं करीये और अपने आपको सुरक्षित रखते हुये कार्यवाही करीये इस देश की राजनीति आपको केवल श्रद्धांजली देने के अलावा कोई नहीं है। आपको श्रद्धांजली दिया जायेगा, मुश्कुराया जायेगा और खाकर चला जायेगा और फिर प्रचार-प्रसार करने लगेगा, उनको यह लगता है कि इस देश के अंदर कुछ हुआ ही नहीं है। इस ई.आई.ए. में तो कितने ग्राम प्रभावित होंगे ये भी नहीं लिखा है। बंजारी मंदीर आस्था का केन्द्र था लेकिन इसे जनसुनवाई का मंच बना दियें। रायगढ़ जिले का पाली गांव अनुसूचित क्षेत्र के बाहर आता है और जनसुनवाई अनुसूचित क्षेत्र में हो रहा है। प्रशासन की जिम्मेदारी है की ई.आई.ए. टी.ओ.आर. के हिसाब से बनी है की नहीं। अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के तहत आवेदन जमा के 45 दिवस के अन्दर जनसुनवाई कराना होना होता है, लेकिन यह तो एक वर्ष से अधिक हो गया है। यहां से पाली 08 कि.मी. दूर है जहां जनसुनवाई हो रहा है तो इस अप्रैल में गर्मी में वहां के लोग कैसे आयेंगे। अनुकूल परिस्थिति

नहीं है तो यह जनसुनवाई क्यों। आज जो 500-600 लोग यहां आये थे वो कोरोना से मृत्यु होती है तो क्या कलेक्टर इसके जिम्मेदार होंगे। प्रभावित क्षेत्र 56 गांव है और ई.आई.ए. सिर्फ 06 गांव जाती है, एस.डी.एम. घरघोड़ा, कलेक्ट्रेट रायगढ़ जाती है लेकिन रायगढ़ एस.डी.एम. में नहीं जाती। इनका बहाना है कि कोरोना काल में गांव-गांव में जाकर ई.आई.ए. पहुंचाना संभव नहीं है लेकिन जनसुनवाई में बुलाना संभव है। बाहर में एक-एक बस में 70-80 व्यक्तियों को लेकर लाया लेजाया जा रहा है। पिछले कई जनसुनवाई इसी जगह में हो रही है लेकिन ई.आई.ए. रिपोर्ट में कही 43 प्रभावित गांव है, कही 40 गांव, कही 56 है। यहां लोगो के साथ मजाक और खिलवाड़ हो रहे है। 14.09.2006 अधिसूचना में कहीं नहीं लिखा है कि कोई अपनी बात 10-15 मिनट में बोले। यहां नलवा के जनसुनवाई का डाटा आज भी ई.आई.ए. में चल रहा है। यहां ग्रामीण जनता की संख्या 42000 आस-पास है, आंगनबाड़ी में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, जल-जंगल की क्या स्थिति है ये सब ई.आई.ए. में दर्शित नहीं है। हर्षा बेहरा, तेन्दु पत्ता आदि पहले आदिवासी लोगो का जीवन यापन का साधन था जिसे पुरा समाप्त कर दिया गया है। जिन आदिवासी समुदाय के जमीन पर उद्योग स्थापित होता है तो उन पर कोई परिवर्तन नहीं आया है। एक सरपंच ने बताया कि उद्योगपति में कहा कि मुझे एनओसी नहीं दोगे तो सरपंच पद से हटवा देंगे। रायगढ़ जिले में पहले सड़क की स्थिति और आज की स्थिति से बहुत अच्छा था। एजुकेशन का स्तर 1994 के समय में किरोड़ीमल को हटा दिया जाये तो रायगढ़ जिला में एक भी इंजीयरिंग कालेज नहीं बना हास्पिटल नहीं बना। कागजो में जितना विकास करते है की लोग सोने-चांदी की सड़को में चलेंगे। 356 करोड़ रुपये डी.एम.एफ. में है, फिर भी सड़क नहीं है। प्रदूषण मापक यंत्र एवं डेससबोर्ड आज तक नहीं लगा, कैसे पता चलेगा कि यहां पी.एम. 10, पी.एम. 2.5 की मात्रा कितनी है। विकास बाद में करना पहले स्वास्थ्य के बारे में तो सोच लों। कलेक्ट्रेट के उपर लगवा दो, एक मापक यंत्र लगा है जिंदल में। मैं 14.09.2006 क अनुसार अपनी टीका टिप्पणी रखने आता हूँ। ग्रामपंचायत सराईपाली, विकासखण्ड तमनार जहां दो सिलका का खदान लगे हुये है, जिससे सिलिकोशिस बीमारी होता है। जहां स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया तो 12 लोग इस बीमारी से ग्रसीत पाया गया जिसमें से 02 की मौत भी हो गई, लेकिन यह सब ई.आई.ए. में दर्ज नहीं है। पर्यावरण विभाग द्वारा निरीक्षण में नोटिस दे दिया जाता है और एक सप्ताह में उसे संचालन का परमिशन भी दे दिया जाता है। हमारा एन.जी.टी. का केन्द्र भेपाल है जहां कोई जज नहीं है। एन.जी.टी. के 05 सदस्य की टीम ने रायगढ़ जिले का अध्ययन किया और एन.जी.टी. ने नये उद्योग की स्थापना और विस्तार नहीं किया जाना है आदेशित हुआ लेकिन ये जनसुनवाई क्यों। इन 03 महिना के अन्दर जितनी जनसुनवाई हुआ है जिसे हम एन.जी.टी. खुद लेकर जायेंगे। हम भी चाहते है की उद्योग स्थापित हो, रोजगार मिले, स्थानीय लोगो का विकास हो, लेकिन जो क्लीयरेंस मिला है उसका पालन तो करें। एक ई.एस.पी. को चलाने में 500-700 रु. की लागत आती है लेकिन उसे बचाने के लिये लाखो लोगो की जिंदगी दाव में लगाते है। लोगो के साथ खिलवाड़ मत करें। हमारी गाड़ी का इण्डिकेटर टुट जाता है तो पुलिस 500 का जुर्माना काट देती है और उद्योग इतनी बड़ी आपराधिक कार्य कर रही है तो पुलिस उसका प्रोटेक्शन करती है। केलो नदी पर फ्लाई ऐश का मामला था उसे हमने पर्यावरण विभाग भेजा उसमें तुरन्त कार्यवाही हुआ। आप और हम मिलकर पर्यावरण की रखवाली का कार्य करेंगे तो रायगढ़ का विकास कार्य एवं स्थिति अनुकूल हो

जायेगा। आप जंगली जानवर के संरक्षण, बिजली पानी, रोजगार, स्वास्थ्य के बारे में काम करे, हम आपके साथ है। मैं समर्थन या विरोध करने नहीं आता। मैंने रेड्डी साहब से बोला किसी भी उद्योग के जनसुनवाई से पहले मिलकर एक ऐसा ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें सभी डाटा रहेगें। 18 करोड़ पेड़ लगाया गया है तो मैंने वन मण्डलाधिकारी से पुछा तो वो बता नहीं पाये। इससे अच्छा है कि काम कम करें और बेहतर करें। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और प्रशासन आज इस दिवस पर बहुत अच्छा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है।

457. इनोसेन कुजुर, बहुजन समाज पार्टी, — जिला प्रशासन द्वारा अभी कोरोना काल में धारा 144 लगा हुआ है। अभी 5 आदमियों से ज्यादा लोग एक साथ रहने को नहीं है और यहां जन सुनवाई में भीड़ गला है। मेरा पुरा विरोध है। खेल कुद, सांस्कृतिक प्रोग्राम, स्कूल, जुलूस, रैली, धरना सब आगामी आदेश तक प्रतिबंध रहेगा। हमारा अनुरोध है कि इसे रद्द किया जाये। कल कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कंपनी का समर्थन हम करेंगे लेकिन पर्यावरण का ध्यान दिजीए, रोजगार दिजीए। किसी प्राकर का मशीन नहीं चालाया जाता है प्रदूषण को रोकने के लिये। ग्राम पंचायत की अनापत्ति के बिना जन सुनवाई कराई जा रही है। प्रभावित स्थानीय लोगो को पुर्नवास, मुआवजा, रोजगार की व्यवस्था किया जाये। ये पाली का जन सुनवाई है तो इससे वहीं होना चाहिए। ये मिली भगत है प्रशासन के साथ। पहले रोड़ कैसा था पर्यावरण केसा था ओर आज कैसा है।

458. राजेश नायक, कुसमुरा — पर्यावरण अधिकारी एवं अन्य अधिकारी गण सब बिन्दु को सुनते हैं तो उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं होगी। हमारे देश का कानून और सविधान को बौना बना दिया गया है जिस पर विकास का दौर भारी पड़ रहा है। मानव जाति को बचाने के लिये आज विश्व में जो पहल हो रही है और हम यहां काले धुआ चिमनीयों में है उसे सुधारना होगा। गांव में जो बिमारी हो रही है उसके तो लक्षण भी नहीं मालुम हो रहा है। इस क्षेत्र के जो साग-सब्जी में जो गुणवत्ता पहले थी वो आज नहीं रही है। जल/वायु प्रदूषण के माध्यम से साग-सब्जी में उर्वर और पोष्टीक समाप्त हो गई है। आज मनुष्य की हसी को समाप्त हो गई प्रदूषण से और मनुष्य चिड़चिड़ा हो गया है। उद्योगपति यहां नहीं रहते यहां का पानी/हवा को ग्रहण नहीं करते तो क्या जानेगें। पहले हम इस एरिया में पौधे को देखते थे हरा भरा था आज हरियाली तो दिख ही नहीं रही जो कोयले के धुओं से काली हो गई है।

459. राजेश गुप्ता, सराईपाली — आज पहली बार हमारे गांव में ई.आई.ए. रिपोर्ट मिला। पहले नहीं जाता था। मैंने पढ़ा जिसमें इस क्षेत्र के बारे कम और अन्य क्षेत्र के बारे में ज्यादा बात है। जिसमें पाली गांव का कोई बात नहीं है। देलारी गांव में झरना है उसका जिक्र नहीं है। पाली में तालाब है जिसमें पलाई डाला जाता है। हमारे गांव में सिलिकोशिसाश बिमारी है जिसमें मैं काम काम करता हूं। यहां कोई स्वास्थ्य कैम्प नहीं लगाया जाता है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है जिसमें स्वास्थ्य कैम्प लगाना चाहिए उस समय में जन सुनवाई करा रहे हैं तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। यहां लगभग 500 लोग आये हैं। हमें शुद्ध वातावरण में जीने व शुद्ध पानी पीने का अधिकार है। इसके लिये हम कलेक्टर साहब से शिकायत देते हैं तो कोई कार्यवाही नहीं होती। आप एसी गाड़ियों आते हैं तो आपको कहां पता चलेगा। हमारा क्षेत्र भयानक स्थिति में है। आप एक दिन हमारे गांव में रह कर देखिये तब पता चलेगा। मुझे नहीं चाहिये ऐसा विकास जो में

जान को जोखिम करे। मैं सभी कंपनियों का विरोध करता हूँ। प्रत्येक दिन हम जब निकलते हैं तो हमारा पैर काला हो जाता है प्रत्येक कंपनी 40-50 बोर चलाता है और किसान को एक बोर की अनुमति नहीं है। सारे तालाब सुख गये हैं। आज आप हमारे स्थिति को समझिये हम और विकास नहीं चाहते हैं।

460. सुनील मिंज, सर्व आदिवासी संघ, रायगढ़ - मैं इस जन सुनवाई का विरोध करता हूँ। बिना ग्राम सभा के सहमति के यह जन सुनवाई हो रहा है। हम केश दायर करेंगे।
461. राधेश्याम शर्मा, रायगढ़ :- आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर भारत देश के जिला रायगढ़ के प्रशासन जो इतिहास रचा है उसे कोई भुला नहीं पायेगा। जो छत्तीसगढ़ की स्थिति और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों को प्रतिबंध दिया गया है आगामी आदेश तक। क्या कलेक्टर महो. के आदेश की अवहेलना करने के लिये यह जन सुनवाई हो रही है। मैंने पुछा कलेक्टर साहब से कि 09 फर्जी जन सुनवाई आपके द्वारा कराई गई है। अभी जितने 10 जन सुनवाई हो चुकी हैं उसका मुल्यांकन कराये और केन्द्रीय मंत्रालय रिपोर्ट पहुँचाया जाये। इस जन सुनवाई को यही निरस्त किया जाना कानून और जन हित के लिये सही है। कंपनी के कंसल्टेंसी से आप पुछ लीजिए की किस किस जगह से मिट्टी/पानी का सेम्पल लिया गया है और कौन कौन गांव से पंचनामा किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस जन सुनवाई को यही पर विराम दे निरस्त करें। कानून को दृष्टिगत रखते हुये इसे निरस्त करें। कटारा साहब भी भ्रष्ट हैं मैं उन्हें दण्डित कराऊंगा। न्यायिक प्रशासनिक लोग भ्रष्ट हो रहे हैं। जन सुनवाई सुनने और बोलने का नहीं है न्याय देने का है। आप न्याय दीजिए। इनके द्वारा फर्जी ई.आई.ए. फर्जी दस्तावेजों को प्रयोग किया गया है जो आपराधिक है। जब तक रायगढ़ का पर्यावरण प्रभाव का मुल्यांकन नहीं हो जाता है तब तक नये एवं विस्तार उद्योग का नहीं होना चाहिए। क्या इस जन सुनवाई के लिये राष्ट्रपति के द्वारा या राज्य पाल का सहमति है। उद्योगपति करोड़ों रुपये देकर लोगों के जीवन का खिलवाड़ कर रहे हैं। रायगढ़ जिला में आधा दर्जन से अधिक दण्डाधिकारियों ने जन सुनवाई को निरस्त किया है। जन सुनवाई विधि संगत नहीं है तो इसे निरस्त करें। क्या कलेक्टर साहब का दोहरा चरित्र है। करोड़ों से मरने वाले तो बाद में मरेंगे यहां सड़क दुर्घटना एवं नक्सलवादियों से लड़ते हुये वीरगति को प्राप्त हुये हैं। लेकिन हम तो कीड़े-मकोड़े की तरह मर रहे हैं। कलेक्टर रायगढ़ के आदेशानुसार शादी विवाह मरने में एक लिमिट लोगों की संख्या दर्ज की गई है लेकिन क्या जन सुनवाई में नहीं है। कटारा साहब भ्रष्ट हैं, चोर हैं उद्योगपतियों के पिट्टु हैं। मैं ये सब बोल रहा हूँ वो केन्द्रीय मंत्रालय भेजने के लिये विडियो में नहीं बोल रहा हूँ। आप भी पिछले अधिकारी की तरह भ्रष्ट मत बनियें। कानून के उल्लंघन में न्यायिक पद पर बैठे अधिकारी मौन हैं तो वो भी उद्योगपति के पिट्टु हैं। मैं मास्क नहीं लगाऊंगा वाला न काटे मेरा। आप कलेक्टर महो. से सलाह ले और जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री से और इस जन सुनवाई को निरस्त करें। रद्द करें। हम न्यायपालिका को वो मानते हैं जो हमें जीवन जीने का अधिकार है। क्या कलेक्टर महो. पता नहीं है क्या कि फर्जी जन सुनवाई हो रही है। न्याय के लिये क्या मैं सशस्त्र ले कर नक्सलियों के साथ मिल जाऊ। सुप्रीम कोर्ट में सारे आदमी भ्रष्ट हैं। मुझे दण्डित करे और जेल भिजवाये नहीं तो इसे निरस्त करें। यहां के 50-50 फीट में गार्डनिंग होना चाहिए। नवीन जिंदल ने इंजीनियरिंग कालेज को सी.एस.आर. से बने हास्पिटल को गर्वनमेंट को हेण्डओवर नहीं

किया है। 14.09.2006 का नोटिफिकेशन है उसे आप पढ़ लीजिए क्या उसके अनुरूप हो रहा है ये जन सुनवाई। यहां जो भी दण्डाधिकारी के पद पर उनसे आप सुझाव सलाह ले ले। रमन सिंह के खिलाफ मैंने याचिका लगा रखा था, तो चीफ जस्टीस ने छुट्टी लेकर चला गया। आप जिला, राज्य एवं केन्द्र सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहें। यहां से 10 कि.मी. की परिधि में रायगढ़ भी है तो वहां ई.आई.ए. रिपोर्ट क्यों नहीं गया है। क्या मुझे न्याय के लिये अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जाना पड़ेगा। आप निर्णय ले साहब। आप कंपनी के कन्सलटेड से पुछिये की कहा कहां से कब कब इन्होंने सैम्पल लिये हैं। छ.ग. की जनता को न्याय दीजिए। आप भी संविधान का पालन नहीं कर सकते, तो जाइयें घर। ई.आई.ए. रिपोर्ट में न तो बच्चों की संख्या, न तो महिलाओं की, न ही सामाजिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक जगहों के बारे में है। बता दीजिए फिर की यहां तानाशाही चलेगा। मैं संविधान को कलंकित नहीं होने दुगां, जिसके लिये हमारे कई नवजवान एवं पुर्वज का देन है। क्या कलेक्टर साहब ने अलग से आदेश किया गया है क्या जन सुनवाई के लियें। इस जन सुनवाई के लिये आप को अलग से अनुमति किसने दिया है। मुझे न्याय, दे साहब। उद्योगों का प्रशासनिक अधिकारियों का जो साठ-गाठ है सामने आना चाहिए। मैं बार-बार निवेदन करता हूँ कि आपने संविधान अनुरूप निर्णय लिया। कलेक्टर महोदय ने मुझे कहा है कि और कोई जनसुनवाई नहीं होगा और आज यह जनसुनवाई हो रही है। मैं न्याय के लिये गोहार कर रहा हूँ और मुझे न्याय दीजिए। नोटिफिकेशन में प्रावधान है कि तीन मौसम में जल, वायु एवं पानी का सैम्पल लेना है। मैं एक जनसुनवाई में आया था तो कटारा साहग गोल हो गये थे जबकि 05 बजे तक होना था और जनता आति है तो एक सप्ताह तक बैठना होगा। कंपनी वाले मेरे घर में मिलने आये थे और बोले साहब एक बार तो मिल लो। कंपनी वाले कोई तो आये और बोले कि यह ई.आई.ए. रिपोर्ट गलत है। पीठासीन अधिकारी महोदय आप जाइये पाली, देलारी मोटर साईकल में आप को पता चल जायेगा कि आप यह जनसुनवाई क्यों करा रहे हैं। मैं पीछे कदम उठाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ मरना पसंद करूंगा, सहादत करूंगा। मैं कानून का इतना जानकार हो गया हूँ कि अब मुझे कानून की पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहा-इस पंडाल में कोई न्याय लेने के इच्छुक नहीं है। जो कानून को समझते हैं वो आये मेरे पास। खड़े कर मुझे सजा मत दीजिए मुझे न्याय दीजिए सर। कलेक्टर साहब ने सायद आपको न्याय देने के लिये भेजा है। क्या यहा शोसल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। मेरे को नहीं लगता कि साहब मुझे तुरंत न्याय देंगे। पीठासीन अधिकारी अगर महामारी अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो वे भी दण्ड के भागीदारी हैं। धार्मिक, राजनैतिक कार्यक्रम सारे बंद हैं तो यह जनसुनवाई कैसे होगी। मैं अब पुलिस अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा और कहूंगा कि ये अपराध कर रहे हैं या नहीं। आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो मैं किससे बात करू। मैं आपको कानून का उल्लंघन करने के लिये क्या आप को मैं छुट दे दू। समापन में प्रश्न पुछने का अधिकार है मेरा। आप क्या कानून जानते हो।

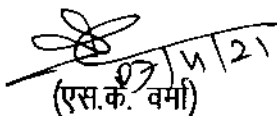
462. सुरेश अग्रवाल - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
463. यश अग्रवाल, गेरवानी - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
464. दीपक अग्रवाल, गेरवानी - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
465. श्यामलाल, गेरवानी - मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।

466. रूपेन्द्र, तराईमाल — मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
467. पद्मलोचन, सराईपाली — मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
468. दुलाराम, तराईमाल — मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
469. रतन सिंह, तराईमाल — मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ।
470. बाबुलाल, पाली — इससे पूर्व ओर भी जन सुनवाई में 2.5 लाख का ग्राम में काम कराने की बात हुई थी अभी तक नहीं हुआ है। भारी वाहनों से पशुओं की मौत होता है। 45 तालाबों का गहरीकरण कार्य के लिये कहा गया लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। हमारे गांव के दो-चार आदमी पैसों के पीछे भागते हैं। रोड़ बनना चाहिए। उसमें पानी छिड़काव होना चाहिए। जितने भी प्लांट है उसमें अग्रोहा स्टील प्लांट बहुत अच्छा है। मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूँ। मेरा 30 एकड़ का जमीन में ही प्लांट बसा है। लेकिन हमारे घर के कोई भी नौकरी नहीं कर रहा है, नौकरी मिलना चाहिए। मां काली द्वारा काम कराउंगा करके पाईप लगा दिया गया है। पैसा साट-घाट करके खा जाते हैं कोई विकास नहीं होता है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस-पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये हैं जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 4:30 बजे कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दों तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

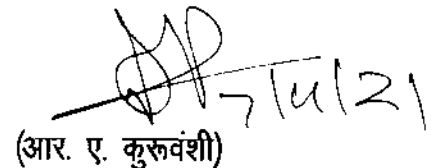
कंपनी कंसलटेंट श्री महेश्वर रेड्डी द्वारा बताया गया कि इण्डकेशन फर्नेश में प्रदूषण के रोकथाम के लिये बैग फिल्टर लगाया जायें। रोजगर में स्थानीय लोगों को दिया जायेगा। 45 दिन का जन सुनवाई में होना है। देलारी तराईमाल, ढिमरापुर रायगढ़ कुल मिलाकर 08 जगहों से रोम्पल लिया है। इसमें सिलिकोशिश उत्पन्न होने का कोई चांस नहीं है। हमें 56 गांव दिखाया गया है वो 10 कि.मी. की परीधी में है।

सुनवाई के दौरान 01 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 02 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात सायं 5:15 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।


(एस.क. वर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़


(आर. ए. कुरुवंशी)

अपर कलेक्टर

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)